भारत सरकार

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2825**

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

14 श्रावण, 1948 (शक)

## 'इण्डिया-एआई' मिशन का कार्यान्वयन

**2825. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः**

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कंप्यूटिंग अवसंरचना, सामान्य कंप्यूटिंग सुविधा और एआई कोष के ब्यौरे सहित 'इण्डिया-एआई' मिशन के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) 'इण्डिया-एआई' मिशन के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले ओडिशा के एआई स्टार्ट-अप्स, शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों का ब्यौरा क्या है तथा प्रदान की गई सहायता की प्रकृति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पूर्वी भारत, विशेषकर ओडिशा में एआई अनुसंधान, कौशल विकास और कंप्यूटिंग अवसंरचना के विस्तार के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत दो वर्षों के दौरान 'इण्डिया-एआई' मिशन के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री**

**(श्री जितिन प्रसाद)**

**(क) से (ग):** भारत की एआई नीति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य एआई से जुड़े जोखिमों का समाधान करते हुए युवाओं के लिए आर्थिक अवसर और रोजगार सृजित करना है।

भारत की एआई रणनीति 300 बिलियन डॉलर के वार्षिक राजस्व और 60 लाख सुदृढ़ कार्यबल के साथ भारत के जीवंत आईटी क्षेत्र पर आधारित है। इंडिया एआई मिशन में सात स्तंभ हैं जिनमें एआई मॉडल का विकास, अनुप्रयोग, डेटासेट, प्रतिभा विकास और किफ़ायती गणना शामिल है।

**इंडियाएआई मिशन के तहत अब तक की प्रगति:**

**किफ़ायती गणना:** कंप्यूट संसाधन स्टार्टअप, एमएसएमई, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक संस्थानों, छात्रों और सरकारी संस्थाओं को इंडियाएआई कंप्यूट पोर्टल (https://compute.indiaai.gov.in) के माध्यम से 40% तक की रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो एक प्रकाशित अंतिम उपयोगकर्ता नीति के तहत पात्रता मानदंड और पहुंच के लिए कार्यप्रणाली को परिभाषित करता है।

- सूचीबद्ध किए गए गणना सेवा प्रदाता: 15
- समर्थित अंतिम उपयोगकर्ताओं/परियोजनाओं की संख्या: 237
- स्वीकृत जीपीयू घंटे: लगभग 93.18 लाख
- एनआईसी डेटा सेंटर, शास्त्री पार्क, दिल्ली में लगभग 1.1 ईएफएलओपीएस का एक उच्च-प्रदर्शन एआई कंप्यूट सिस्टम स्थापित किया जा रहा है।

- ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर सहित ओडिशा स्थित संस्थाओं को हाई-एंड जीपीयू कंप्यूट के लिए रियायती पहुंच आवंटित की गई है।

**<u>इंडियाएआई लैब्स:</u>**

- 27 इंडिया डेटा और एआई लैब्स की स्थापना की गई, जो 3,500 से अधिक छात्रों के लिए प्रशिक्षण का समर्थन करती है।
- आईटीआई/पॉलिटेक्निकों में स्थापना के लिए 188 अतिरिक्त प्रयोगशालाओं की पहचान की गई है।
- नाइलिट डेटा एंड एआई लैब, भुवनेश्वर: नाइलिट केंद्र, भुवनेश्वर में वन इंडियाएआई डेटा एंड एआई लैब का संचालन किया गया है, जो डेटा एनोटेशन और डेटा क्यूरेशन में मूलभूत पाठ्यक्रम प्रदान करता है। भुवनेश्वर केंद्र में दो मूलभूत पाठ्यक्रमों के लिए 374 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 199 छात्रों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

**<u>एआई उत्कृष्टता केंद्र:</u>** इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग पिलर के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और उद्योग भागीदारों के सहयोग से 58 एआई उत्कृष्टता केंद्रों (एआई-सीओई) की स्थापना के लिए एक योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना में ओडिशा में 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना का प्रावधान शामिल है।

**(घ):** पिछले दो वर्षों के दौरान इंडियाएआई मिशन के तहत बजटीय आवंटन निम्नानुसार है:

| # | वित्तीय वर्ष | बजटीय आवंटन (करोड़ रुपये) |
|---|---|---|
| 1 | 2024-25 | 173 |
| 2 | 2025-26 | 800 |

*****